दैनिक जागरण
कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं

राहुल की जुमलेबाजी

पता नहीं राहुल गांधी को यह आभास हुआ या नहीं कि योग दिवस पर उनकी ओर से जो तंज भरा ट्वीट किया गया उसकी कैसी खराब प्रतिक्रिया हुई, लेकिन बेहतर यह होगा कि उनके करीबी उन्हें बताएं कि उन्होंने किस तरह एक अवांछित टिप्पणी करके यह उम्मीद ध्वस्त कर दी कि एक और करारी पराजय के बाद वह अपनी रीति-नीति में सुधार करने में सक्षम होंगे। उनके अरुचिकर ट्वीट से यही जाहिर हुआ कि उन्हें योग दिवस की महत्ता के साथ देश की समृद्ध विरासत और गरिमा की भी परवाह नहीं। निःसंदेह राहुल गांधी के अलावा अन्य अनेक लोग भी ऐसे हैं जिन्हें यह रास नहीं आया कि नरेंद्र मोदी की एक पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने योग दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का फैसला किया और देखते ही देखते ही वह दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया, लेकिन आम तौर पर ऐसे लोग अपनी नापसंदगी इसलिए प्रकट करने से बचते हैं, क्योंकि वह इससे परिचित हैं कि योग मानव समाज को एक अप्रतिम देन है और उससे भारत की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। अगर राहुल गांधी को योग दिवस पर होने वाले आयोजन पसंद नहीं तो वह चुप रह सकते थे, लेकिन मोदी सरकार पर तंज कसने की ललक में उन्होंने यह ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा कि वह अपनी फजीहत ही कराएंगे। क्या इससे खराब बात और कोई हो सकती है कि जब दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा था तब देश की सबसे पुरानी पार्टी के अध्यक्ष ने उसका उपहास उड़ाना बेहतर समझा? ऐसा करते समय उन्होंने यह भी ध्यान नहीं रखा कि वह मोदी सरकार के साथ सेना का भी निरादर करते हुए दिखेंगे।

आखिर किसी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, जो प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है, योग को लेकर ऐसी सस्ती और हल्की टिप्पणी कैसे कर सकता है? क्या सेना के जवानों संग योग करते कुत्तों की फोटो के अलावा उन्हें और कुछ ऐसा नहीं दिखा जिस पर वह जुमलेबाजी करने का अपना शौक पूरा कर सकते? आखिर ऐसी कोई फोटो नए भारत का परिचायक क्यों नहीं हो सकती? योग दिवस पर राहुल गांधी का कटाक्ष भरा ट्वीट उनके खराब हास्यबोध के साथ उनकी सतही राजनीतिक समझ को भी बयान करता है। यह ट्वीट न केवल यह रेखांकित करता है कि राहुल गांधी को मोदी सरकार के साथ उसके नए भारत के नारे से भी चिढ़ है, बल्कि यह भी कहता है कि उन्हें अब तक यह अहसास नहीं हो सका है कि कांग्रेस को इतनी करारी पराजय का सामना क्यों करना पड़ा? शायद इसी अहसास के कारण वह यह साबित करने की कोशिश करने में लगे हुए हैं कि नरेंद्र मोदी ने नफरत फैलाकर सत्ता हासिल कर ली। जब सत्तापक्ष प्रचंड बहुमत से लैस हो और राष्ट्रीय दल के रूप में केवल कांग्रेस ही उसे चुनौती देने में थोड़ा-बहुत सक्षम दिखती हो तब विपक्ष की अगुआई करने वाले राहुल गांधी के लिए तो यह और जरूरी हो जाता है कि वह कहीं अधिक धीर-गंभीर रहें और बेहद जिम्मेदारी से खुद को प्रभावी बनाने के तौर-तरीके अपनाएं। अफसोस की बात है कि राहुल गांधी ने ठीक इसके उलट काम किया।

उत्तराखंड की अपेक्षाएं

हिमालयी राज्यों के लिए नीति आयोग में अलग प्रकोष्ठ का गठन किया जा चुका है। उम्मीद की जानी चाहिए कि विषम भौगोलिक क्षेत्र के साथ पर्यावरणीय बंदिशों और सीमित आर्थिक संसाधन से जूझ रहे हिमालयी राज्यों के बारे में अब नीतिगत स्तर पर फैसले किए जा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमालयी राज्यों के संदर्भ में उनकी जरूरतों पर जोर देते हुए विशेष नीतियों का समर्थन कर चुके हैं। नीति आयोग में गठित यह प्रकोष्ठ उसी दिशा में एक कदम माना जा रहा है। हिमालयी राज्यों के बारे में लंबे अरसे से विशेष नीति नियोजन की पैरवी की जाती रही है। विषम परिस्थितियों और क्षेत्रफल की वजह से इन राज्यों में बुनियादी ढांचे पर अलग तरीके से फोकस किए जाने की दरकार है। पर्यटन, बागवानी, परंपरागत फसलें, हस्तशिल्प के साथ ही ऊर्जा के पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोतों के विकास को प्रोत्साहित कर इन राज्यों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। जिन बुनियादी क्षेत्रों में विकास की संभावनाएं हैं, उन्हें अभी तक राष्ट्रीय नीति का हिस्सा बनाया नहीं जा सका है। इन सभी पर्वतीय राज्यों खास तौर पर उत्तराखंड को केंद्र की सत्ता पर दोबारा आसीन मोदी सरकार के पहले बजट से काफी उम्मीदें हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा में राज्य सरकार ने अपनी जरूरतों को रखा भी है। पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से यहां निर्माण कार्यों की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यही वजह है कि केंद्र पोषित योजनाओं में पर्वतीय राज्यों के लिए अलग मानक निर्धारित किए जाने की पुरजोर पैरवी की जाती रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में अड़चन आवास निर्माण की ज्यादा लागत है। राज्य सरकार ने इस लागत को 1.30 लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को कामयाब बनाने के लिए मनरेगा के तहत अतिरिक्त मानव दिवस सृजित करने की मांग की है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में ग्रामीण आबादी का मानक 250 से घटाकर 150 किए जाने के साथ ही इस योजना में रोपवे को भी हिस्सा बनाने की पैरवी की गई है। वर्ष 2021 में हरिद्वार में होने वाले महाकुंभ और राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए भी राज्य केंद्र से वित्तीय मदद की उम्मीदें बांधे हुए है।

तीव्र विकास की चुनौतियां

संजय गुप्त

तेजी से उभरते किसी भी देश में एक सक्षम न्यायिक तंत्र भी होना चाहिए। अगर न्याय समय से न मिले तो फिर वह बेमानी हो जाता है

अवधेश राजपूत

मोदी सरकार की दूसरी पारी की शुरुआत हो चुकी है। अगले पांच साल में यह सरकार किस तरीके से विकास और सामाजिक सौहार्द की दिशा में काम करेगी, इसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में साफ दिखी। भाजपा ने 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में जो मुख्य बातें रखी थीं लगभग उन सबका उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में दिखा। इस अभिभाषण के जरिये प्रधानमंत्री मोदी ने एक तरह से घोषणा पत्र के प्रति अपनी संकल्पबद्धता फिर से प्रकट की। चुनाव नतीजों के बाद मोदी ने यह जो कहा था कि उनकी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के आधार पर चलेगी उसे अगर राष्ट्रपति ने भी रेखांकित किया तो इससे सरकार की प्रतिबद्धता ही प्रकट होती है। भारत में हर नागरिक को एक समान दृष्टि से देखने और बिना भेदभाव उसके विकास में सहायक बनने की बात भी भाजपा के घोषणा पत्र में थी। तत्काल तीन तलाक पर नया विधेयक इसी घोषणा के अनुरूप है। पिछली बार यह विधेयक संसद से पारित नहीं हो सका था, लेकिन सरकार ने अध्यादेश लाकर यह साफ कर दिया था कि वह इस मसले पर अपने कदम पीछे खींचने वाली नहीं। मोदी सरकार जिस तरह देश की सुरक्षा को शीर्ष पर रखने के साथ ही एनआरसी पर जोर दे रही है उससे यही पता चलता है कि यह मुद्दा भी सरकार की प्राथमिकता सूची में है। यह तय है कि सरकार की प्राथमिकता वाले कई मुद्दे कुछ राजनीतिक दलों को रास नहीं आने वाले। इसकी पुष्टि तीन तलाक संबंधी विधेयक पर कांग्रेस और वामदलों की आपत्ति से होती है। यह स्पष्ट है कि सरकार ऐसी आपत्तियों की परवाह करने वाली नहीं। उसे करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह इन्हीं मुद्दों के सहारे भारी बहुमत से जीत कर आई है।

इस समय कई सेक्टर आर्थिक मंदी से ग्रस्त दिख रहे हैं। इसके कई कारण हैं, लेकिन एक बड़ा कारण करीब तीन माह लंबी चुनाव प्रक्रिया रही। यह किसी से छिपा नहीं कि चुनावी आचार संहिता सरकारी कामकाज को लगभग ठप करने का काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी एक अर्से से यह कहते रहे हैं कि बार-बार के चुनावों से देश को छुटकारा मिलना चाहिए, क्योंकि इसके कारण शासन संचालन बाधित होता है। पांच साल के कार्यकाल में ढाई से तीन महीने लोकसभा चुनाव में निकल जाते हैं और फिर विधानसभा चुनावों में भी अच्छा-खासा समय खपता है। लोकसभा चुनाव बाद रह-रह कर तीन या चार विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होते रहते हैं। हर चुनाव प्रक्रिया लगभग एक माह का समय लेती है। इस दौरान भी शासन-प्रशासन के काम रुक जाते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जहां कई पुराने नियम-कानूनों में बदलाव करने और प्रशासन पर सतत निगाह रखने की जरूरत होती है वहां अगर पांच साल के कार्यकाल में रह-रहकर होने वाले चुनावों के कारण करीब साल-डेढ़ साल का समय आचार संहिता की भेंट चढ़ जाए तो यह देश की क्षति ही है। आखिर जब इतने समय सरकारी कामकाज ठप से रहेंगे तो फिर अपेक्षित विकास कैसे संभव है? लोकतंत्र में चुनाव आवश्यक हैं, लेकिन यह ठीक नहीं कि बार-बार के चुनाव विकास गति धीमी करने का कारण बनें। इसी धीमी गति के कारण भारत कई विकासशील देशों से पीछे है। यह साफ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक साथ चुनावों पर बल इसीलिए दिया गया, क्योंकि वे समय की मांग हैं। इसी मांग पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री ने बीते दिनों सर्वदलीय बैठक बुलाई। यह अजीब है कि कई दलों ने इस बैठक में भाग लेना भी जरूरी नहीं समझा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका भी उल्लेख है कि मोदी सरकार देश को पांच लाख ट्रिलियन डॉलर यानी करीब साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इस समय भारत की अर्थव्यवस्था लगभग दो सौ लाख करोड़ रुपये के आसपास है। अगले पांच साल में इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अर्थव्यवस्था में तमाम सुधार भी करने होंगे और मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। इसी के साथ किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य पर भी नए सिरे ध्यान केंद्रित करना होगा। किसानों में यह भरोसा जगना चाहिए कि यह लक्ष्य उनके करीब आ रहा है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका भी खास तौर पर उल्लेख किया गया कि मोदी सरकार लोगों को इस तरह सशक्त करेगी ताकि वे न तो सरकार के बोझ के तले दबें और न ही सरकार की कमी को महसूस करें। इसके लिए लालफीताशाही को कम करने और तकनीक के उपयोग से जनता को सरकारी सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। बेहतर होगा कि मोदी सरकार देश को आगे बढ़ाने की कोई रूपरेखा बनाकर उसे जनता के सामने पेश करे। इस रूपरेखा में कानून एवं व्यवस्था में सुधार को भी शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि हम इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि पुलिस का ढांचा और उसकी कार्यशैली कैसी है? पुलिस भ्रष्टाचार से भी ग्रस्त है और वह संसाधन के अभाव का भी सामना कर रही है। बात केवल पुलिस की ही नहीं, सीबीआइ, ईडी और अन्य अनेक सरकारी एजेंसियों की भी है। प्रधानमंत्री ने अपने कार्यालय के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्हें प्रभावी नहीं, बल्कि कार्यकुशल और दक्ष होने की जरूरत है। फिलहाल इसकी कमी ही दिखाई पड़ती है। समस्या यह भी है कि नौकरशाही जवाबदेही के दायरे से भी दूर है। ऐसे में नौकरशाही में सुधार को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

तेजी से उभरते किसी भी देश में एक सक्षम न्यायिक तंत्र भी होना चाहिए। अगर न्याय समय से न मिले तो फिर वह बेमानी हो जाता है। न्यायपालिका का हाल किसी से छिपा नहीं। बीते कुछ समय से तो सर्वोच्च न्यायालय ही तमाम सवालों के घेरे में है। उसकी सरकार से खटपट भी चलती रहती है। यह खटपट तेज विकास के एजेंडे में बाधक बन सकती है। आखिर इसका क्या मतलब कि सरकार के हर फैसले को अदालत में चुनौती दी जाए? अगर हर सरकारी फैसले की न्यायिक समीक्षा होगी तो फिर उनके अमल में देरी होना तय है। हमारी अदालतें मुकदमों के बोझ तले दबी हैं। यह बोझ हाल-फिलहाल कम होता नहीं दिख रहा है। विडंबना यह है कि तमाम मुकदमों में एक पक्ष केंद्र अथवा राज्य सरकारें हैं। क्या यह उचित है कि सरकारें जनता से मुकदमेबाजी में उलझें? आज आम आदमी को यह भरोसा मुश्किल से होता है कि उसे समय पर न्याय मिल पाएगा। इस कारण वह अन्याय का सामना करने के बावजूद अदालतों का दरवाजा खटखटाने में हिचकिचाता है। अगर लोगों को त्वरित न्याय मिलने का भरोसा नहीं होगा तो फिर उनका न्यायपालिका पर तो भरोसा कम होगा ही, देश तेजी से तरक्की भी नहीं कर पाएगा। मोदी ने लोकसभा चुनाव नतीजों बाद अपने पहले भाषण में कहा था कि देश में दो ही तरह के लोग हैं- एक गरीब और दूसरे वे जो गरीबी दूर करने में मददगार बनना चाहते हैं। सरकार को ऐसे उपाय करने के लिए सक्रिय होना चाहिए जिससे सरकार और उन लोगों के बीच की दूरी मिटे जो गरीबी दूर करने में सहायक हैं। जब ऐसे लोग सरकार पर भरोसा करने को तैयार होंगे तभी तेज विकास की नींव डालने और देश को साढ़े तीन सौ लाख करोड़ रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने में आसानी होगी।

response@jagran.com

काम न करने के फायदे

हास्य-व्यंग्य

सूर्यकुमार पांडेय

उनका ध्येय वाक्य है, राष्ट्रीय संसाधन बचाना ज्यादा जरूरी है, भले ही हफ्तों का काम महीनों में हो

वह एक सरकारी कार्यालय के मुलाजिम हैं। वैसे तो उनका असली नाम कुछ और ही है, लेकिन चूंकि वह प्रत्येक पत्रावली में कोई न कोई झंझट खड़ा कर दिया करते हैं। इस नाते उनका नया नाम झंझटानंद प्रचलित हो चुका है। चूंकि वह एक सरकारी सेवक हैं, इसलिए आरामतलबी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। उन्होंने जब से अपना पदभार संभाला है, सदैव कार्य को भार मानते रहे हैं। कर्तव्य से मुंह चुराना और अधिकार में सबसे पहले मुंह मारना अपनी बपौती समझते हैं। यह कला उन्होंने स्वयं नहीं विकसित की है। इसे उन्होंने बरसों की लापरवाह साधना के पश्चात अपने सहकर्मियों से हासिल किया है। यह बात भला कौन नहीं जानता है कि सरकारी नौकरी में कामचोरी उस विरासत की मानिंद हुआ करती है, जिसे सेवानिवृत्त होकर जाने वाला व्यक्ति अपने उत्तराधिकारी को कार्यभार के तौर पर भेंट देकर विदा होता है।

बाबू झंझटानंद ने भी यह संकल्प ले रखा है कि वह भी अपने रिटायरमेंट तक सरकारी कार्यालयों में आरामतलबी की इस सुदीर्घ परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने में कोई कोर-कसर नहीं उठा रखेंगे। वह इस शाश्वत सिद्धांत में विश्वास रखते हैं कि अपने मतलब की परंपराएं हमेशा जीवित रहनी चाहिए। उनसे कोई इतना भर कह दे कि बाबूजी, जरा मेरा काम जल्दी कर दीजिए, तो वह मुस्कराते हुए कहते हैं, 'तुमने सुना ही होगा, जल्दी का काम शैतान का। तो क्या मैं शैतान हूं कि जल्दी से तुम्हारा काम कर दूं!' तब अगले आदमी को भी कहना ही पड़ता है कि नहीं बाबू जी, आप तो मेरे लिए देवता समान हैं। इतना सुनना होता है कि बाबू झंझटानंद बोल पड़ते हैं, 'अब जब तुम मुझे देवता समान मान ही रहे हो, तो फिर तुम मेरे साथ भी वैसा ही आचरण क्यों नहीं करते हो?' यह सुनने के बावजूद अगला भी यदि अपनी अक्ल किसी बैंक के लॉकर में रखकर नहीं आया होता है तो फटाफट समझ लेता है कि इस देवता को कैसे खुश करना है! किसी देवता से अपना मनोरथ सिद्ध कराना होता है तो सबसे पहले उसे चढ़ावा तो चढ़ाना ही पड़ता है। इधर चढ़ावा मिलता है, उधर बाबू झंझटानंद की कृपा बरस जाती है। वह अल्प भेंट में ही तत्काल प्रसन्न हो लेते हैं। यह तक नहीं देखते हैं कि उस चढ़ावे का परिमाण कितना है? सूखा-गीला कुछ भी चढ़ जाए, दोनों में सुखी। सूखे मेवे या मिठाई में भी उतने ही गदगद रहते हैं। हां, यदि गुलाबी नोट आ गए, तब उनके गालों की गुलाबी रंगत देखते ही बनती है।

कहते हैं कि उन्होंने नोट कभी गिनकर नहीं लिए। गिनने का काम हमेशा उनकी श्रीमती जी ही करती हैं। वह मात्र लेना जानते हैं। देना नहीं। अगर किसी को कुछ देना ही पड़ जाए, तो वह एक ही चीज देना जानते है और वह चीज होती है टेंशन। किसी का कोई सीधा-सा काम हो, वह उसमें भी अपनी अंगुली टेढ़ी कर ही लेते हैं। फिर ठहाके लगाते हुए कहते हैं, 'पुराने जमाने में अंगुली टेढ़ी किए बिना घी नहीं निकलता था, अब मलाई नहीं निकलती है।' वह मलाई निकालने की कला में तो माहिर हैं ही, अपने से ऊपर वालों को मलाई चटाने में भी उतने ही पारंगत है। क्या ही आलीशान और तनावमुक्त जीवन जीते हैं बाबू झंझटानंद। वह अपने पड़ोसियों और सहकर्मियों की सहज ईर्ष्या को ताक पर रखने के बजाय ठेंगे पर रखते हैं। वह प्रायः कहते हैं, 'अजी, किस-किस की परवाह की जाए? जिसे देखो, वही खोपड़ी पर चढ़कर अपना काम करवाना चाहता है। आज पचास लोगों का काम कर दो तो कल उससे दोगुनी लंबी लाइन खड़ी मिलेगी। इसलिए हमेशा ही अपनी सीट का काम खरामा-खरामा करने की आदत डालनी चाहिए। वैसे भी हर सरकारी दफ्तर का अपना एक सिस्टम हुआ करता है। कुछ नियम-कायदे होते हैं। ढेरों शासनादेश रहते हैं। जरा भी चूक जाओ तो कानून का उल्लंघन हो सकता है। लोग तो चाहते ही हैं कि उनका काम धांय-से हो जाए।'

वह यह सुनिश्चित करते हैं कि भूले से भी कहीं कोई गलती न रह जाए। इसके पीछे वह तर्क देते हैं कि अगर छोटी सी भी गलती हो जाती है तो फिर विभागीय जांच का सामना करना पड़ता है और जब ऐसा होता है तो सरकारी संसाधनों की बर्बादी होती है और देश तरक्की नहीं कर पाता। उनका ध्येय वाक्य है कि राष्ट्रीय संसाधन बचाना ज्यादा जरूरी है, भले ही हफ्तों का काम महीनों में हो। इधर जब से सरकार ने यह कह दिया है कि कोई भी फाइल किसी टेबल पर दो दिन से अधिक नहीं अटकनी चाहिए तबसे उनका ब्लड प्रेशर हाई रहने लग गया है और वह यह कहने लगे हैं कि यह अफसोस की बात है कि सरकार ही राष्ट्रीय संसाधनों की परवाह नहीं कर रही है।

response@jagran.com

ऊर्जा

सेवा

मनुष्य के मन में सेवा भाव का होना अति आवश्यक है। सेवा मानव जीवन की शोभा है और सही अर्थों में यही ईश्वर की सच्ची अराधना भी है। मनुष्य सेवा भाव से ईश्वर तुल्य हो जाता है। ईश्वर सभी से प्रेम एवं सबके प्रति समभाव रखते हैं और जब मनुष्य भी उनके बताए मार्ग पर चलता है तो वे उससे बहुत प्रसन्न होते हैं। सेवा के लिए उठे हाथ उतने ही महान होते हैं, जितने ईश्वर की प्रार्थना में उठने वाले हाथ होते हैं। दूसरों की सेवा करने वाले जीव पर ईश्वर की सदैव कृपा बनी रहती है। हमारी सेवा से खुश होने वाले लोग हमें प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और दुआएं देते हैं, जिससे हमारे कष्ट अप्रभावी हो जाते हैं। ईश्वर भी हमें कष्ट सहन करने की असीम शक्ति प्रदान करते हैं।

सेवा मनुष्य को सरल और निःस्वार्थ बनाए रखती है। सेवा से मनुष्य के मन में कभी यह विचार नहीं आता है कि किसी चीज पर केवल उसका ही अधिकार है। सेवा में मनुष्य अपने पास उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को दूसरों के साथ निःस्वार्थ बांटता है। सेवा का मतलब भी यही है कि दूसरों में भी हम स्वयं को देखें और उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करें, जैसा हम अपने साथ करते हैं। जब हम खुद के लिए कष्ट-दुख नहीं चाहते हैं तो हमें भी दूसरों के दुखों में उनका सहारा बनना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना का हम जितना विस्तार करेंगे, हमारे जीवन में उतनी सुख-शांति और समृद्धि फैलेगी।

जब तक हम सुख-दुख में एक-दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, तब तक मानव जीवन की सार्थकता भी सिद्ध नहीं होती है। महात्मा गांधी का कहना था कि मेरी एक प्रबल कामना है कि मैं कम से कम एक व्यक्ति का दुख कम कर सकूं। ज्यादातर मनुष्य यही सोचते हैं कि यदि उन्हें दुनिया की सारी सुख-सुविधाएं मिल जाएं तो उनका जीवन स्वर्ग बन जाए। यदि उन्हें ये सुविधाएं मिल भी जाएं तो भी उनका जीवन स्वर्ग नहीं बन सकता है। सुविधाएं मिलने के बाद उनका मन और ज्यादा अशांत हो जाता है, क्योंकि भौतिक चीजों में क्षणिक सुख ही होता है। मन की सच्ची शांति भौतिक सुखों से नहीं, बल्कि मनुष्यों के बीच में रहने से मिलती है। जब हम भौतिक सुविधाओं को त्यागकर दूसरों के दुख-दर्द को कम करने की कोशिश करते हैं, तभी हम असीम सुख और संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं।

शंभूनाथ पांडेय (पूर्व नौसैनिक)

तथ्य-कथ्य | आम का निर्यात (करोड़ रुपये में)

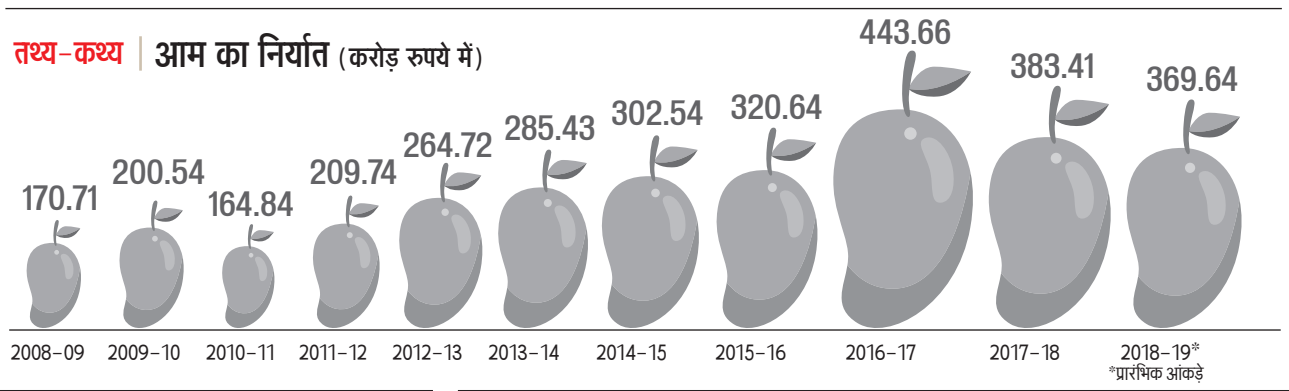

महामारी बनती असंतुलित खुराक

गुकुल व्यास

एक अनुमान के अनुसार दुनिया में होने वाली पांच मौतों में से एक मौत के लिए अपूर्ण या गलत खुराक जिम्मेदार है

ुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले लोग यदि अपने भोजन को संतुलित कर लें तो उन्हें बड़ा ायदा होगा। दुनिया में बीमारियों के बोझ पर कए गए एक विस्तृत अध्ययन में कहा गया है कि ोजन के संतुलित न होने की वजह से कई तरह ी बीमारियां फैल रही हैं। इस अध्ययन में 195 सरकारी नीतियों में सहयोग स्थापित करके दुनिया लोगों के स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए मन्वित प्रयास तत्काल शुरू किए जाने चाहिए। अमेरिका में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के टीट्यूट ऑफ हैल्थ मेट्रिक्स एंड इवोल्यूशन डायरेक्टर डॉ. क्रिस्टोफर मरे ने कहा कि दो शकों से चल रही बहस में नमक, चीनी और ाकनाई पर मुख्य ध्यान दिया जाता है, लेकिन मारा आकलन कहता है कि खाने में अधिक ोडियम के सेवन से या मोटे अनाज, फल-ब्जियों, सूखे मेवों और बीजों के कम सेवन ीमारियां पैदा होने का खतरा रहता है। अध्यय इस पर जोर दिया गया है कि सभी देशों ास्थ खाद्य वस्तुओं के उत्पादन, वितरण अ वन को बढ़ावा देने के लिए व्यापक हस्तक्ष ी आवश्यकता है। इस अध्ययन में 195 दे प्रमुख खाद्य वस्तुओं और पौष्टिक तत्वों उपभोग का आकलन कर पता लगाने की कोशिश हुई कि कैंसर, हृदय रोगों और मधुमेह जैसे गैर-संक्रामक रोगों से होने वाली मौतों पर असंतुलित आहार का क्या असर पड़ा था।

अध्ययन में 1990 से लेकर 2017 के बीच रुझानों पर नजर रखी गई। इस अध्ययन से पहले जनसंख्या के स्तर पर असंतुलित भोजन के स्वास्थ्य संबंधी प्रभावों का आकलन करना मुश्किल था, क्योंकि विभिन्न देशों में आहार के सेवन को वर्गीकृत करने में तमाम पेचीदगियां हैं। नए अध्ययन में आहार के 15 तत्वों पर ध्यान केंद्रित किया गया। इनमें एक आहार में फल-सब्जियों, मोटे अनाज, फलियों, सूखे मेवों, दानों, दूध, रेशों, कैल्शियम, सीफूड ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और पोलीअनसेचुरेटेड फैट्स की मात्रा कम थी और दूसरे आहार में प्रोसेस्ड मीट, चीनी युक्त पेय पदार्थों, ट्रांसफैटी एसिड्सऔर सोडियम की मात्रा बहुत ज्यादा थी। 2017 में हुई 1.1 करोड़ मौतों का कारण असंतुलित भोजन बताया गया है। विश्व में 2017 में हुई आहार से संबंधित मौतों में आधी से अधिक मौतें ऐसे आहार से हुई थीं जिनमें सोडियम अधिक और मोटे अनाज तथा फल की मात्रा कम थी।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

राजरंग

तारीफ के बाद ट्रांसफर का झटका

मंत्रालय के बड़े, मझोले व छोटे अधिकारियों के साथ मंत्री जी की पहली बैठक थी। शुरुआत बड़े जोश के साथ हुई। सभी को कहा गया कि सभी बेहिचक अपने सुझाव दें। यहां कोई छोटा-बड़ा नहीं। इस पर एक युवा अधिकारी ने गजब का उत्साह दिखाया। सुझावों की झड़ी लगा दी। मंत्री जी को भी यह उत्साह बहुत पसंद आया। उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पीठ थपथपाई और यहां तक कहा कि ऐसे ही अधिकारियों की जरूरत है। बैठक आगे बढ़ी। मंत्री जी ने भी एक सुझाव दिया। निश्चित तौर पर यह बहुत ही बेतरतीब सा सुझाव था। सभी पुराने दिग्गज चुप रहे, लेकिन उक्त अधिकारी ने उत्साह में इसे खारिज कर दिया कि ऐसे सुझाव प्रायोगिक नहीं है। पल भर में पूरा मामला पलट गया। मंत्री जी ने उसी समय उक्त अधिकारी का ट्रांसफर कहीं और करने का निर्देश दिया। बैठक समाप्त हुई। अब वह अधिकारी ट्रांसफर रुकवाने की जुगत भिड़ाता घूम रहा है।

छुट्टी में गंवा दिया दफ्तर

कृषि भवन में इस बार मंत्रियों की संख्या बढ़ जाने से उनके बैठने की समस्या हो गई है। नए दफ्तर तलाशे और बनाए जा रहे हैं। इसी अभियान में कई अफसरों के दफ्तर गुम हो गए। यही नहीं, बल्कि उनके कमरों के नंबर तक गायब हो गए। हुआ यूं कि कुछ अफसर गर्मी की छुट्टियों पर गए थे, जिससे उनके दफ्तर में ताला लगा हुआ था। इसी बीच नए मंत्रियों के लिए कमरों की तलाश हो रही थी। एक नायब मंत्री को वही तालाबंद कमरा भा गया। तत्काल आदेश हुआ और कमरे खाली करा लिए गए। अब वहां तोड़फोड़ चल रही है, ताकि नए नायब मंत्री का ऑफिस सजाया जा सके। छुट्टी से लौटे अफसर की यह देखकर सांसें अटक गईं। उन्होंने अपने आला अफसरों को इसकी सूचना दी। पता चला, उन लोगों के पास अब यह विभाग नहीं है। इसका दायित्व किसी और बड़े मंत्री और अफसर को दे दिया गया है, लेकिन हैरानी तो यह है कि उसी विभाग के बड़े मंत्री भी अपने लिए तैयार किए गए ऑफिस में बैठने को राजी नहीं हैं। उनके लिए आवंटित ऑफिस के बाहर नेम प्लेट तक नहीं लग पाई है।

देरी का नुकसान

लोकसभा चुनाव की हार से उबरने की कांग्रेस की कोशिश शुरू होने से पहले ही पार्टी अध्यक्ष के इस्तीफे की फांस में फंस गई है। पार्टी के तमाम दिग्गज नेता जहां अध्यक्ष का इस्तीफा स्वीकार किए जाने के पक्ष में नहीं हैं, वहीं राहुल गांधी अपने इरादे से पीछे हटने को तैयार नहीं। इस रस्साकशी में कांग्रेस की पूरी सियासत ठहर सी गई है। ऐसे में पार्टी के इस मुश्किल दौर में इस्तीफे पर जोर देने के राहुल के फैसले से सबसे ज्यादा असहमत कोई है तो वह हैं सोनिया गांधी। उन्होंने राहुल को यह समझाने का प्रयास भी किया है कि ऐसा हुआ तो आने वाले समय में पार्टी का नियंत्रण गांधी परिवार के हाथ से निकल जाएगा। बताया जाता है कि एके एंटनी समेत दस जनपथ के कुछ चुनिंदा बड़े नेता सोनिया की राय से सहमत हैं और राहुल को मनाने की कोई उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए इस्तीफा स्वीकार कर कांग्रेस के नए अध्यक्ष की ताजपोशी के फैसले में देरी हो रही है। बहरहाल अंदरूनी रस्साकशी की वजह चाहे जो हो कम से कम इसे कांग्रेस को सियासी फायदा तो नहीं मिल रहा।

खुद हुए हैरान

सरकारी काम-काज के वाकये तो आपने तमाम सुने और देखे होंगे। मगर यहां हम एक ऐसे अलहदा वाकये का जिक्र करेंगे जिसे जानकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। हुआ यूं कि पिछले दिनों चौबीसों घंटे काम करने वाले विभाग के मंत्री जी के पास कर्मचारी यूनियन की एक शिकायत मिली। मंत्री जी ने शिकायत को गंभीरता से लिया और तुरंत महकमे के सबसे बड़े अफसर को तलब किया और शिकायत का जवाब पंद्रह दिन में देने को कहा। मंत्री जी का मूड भांपकर अफसर ने भी बिना देर लगाए शिकायत अपने मातहत अफसर को दी और दस दिन में जवाब देने को कहा। कनिष्ठ अधिकारी ने भी ठीक वैसा ही किया। अपने अधीनस्थ को उसे भेजा और मंत्री जी का हवाला देते हुए हफ्ते भर में जबाव देने को कहा। आखिर में यह शिकायत और कई अफसरों के होते हुए महकमे के एक ऐसे कर्मचारी के पास पहुंची जिससे एक घंटे में जवाब देने के लिए कहा गया। अपने वरिष्ठ का आदेश सुनकर पहले तो यह कर्मचारी थोड़ा सकपकाया, लेकिन जैसे उसकी नजर शिकायती पत्र पर पड़ी तो वह भौचक्का रह गया, क्योंकि यह शिकायत तो उसी की भेजी हुई थी।

हन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721
न हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।